RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2022-2024 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
DPR No. N-193
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 3 JANUARY TO 9 JANUARY 2024 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 09 ■ अंक 15 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

राम मंदिर उद्घाटन से इकॉनमी को मिलेगा दम, 50,000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान Page 2

लगातार सातवें महीने जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ के पार Page 3

क्या इंडिया में फिर सजेगी क्रिप्टोकरंसी की महफिल? Page 4

editoria!

भूजल में घातक रसायन

देश के कई हिस्सों से भूजल में घातक रसायनों के होने की खबरें बरसों से आती रहती हैं और इनसे कई तरह की गंभीर बीमारियां भी होती हैं. पर इस समस्या के समाधान के लिए ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं. हाल में छपी एक खबर में बताया गया था कि देश के 25 राज्यों के 230 जिलों के भूजल में आर्सेनिक पाया गया, जबकि 27 राज्यों के 469 जिलों में फ्लोराइड मिला. इसके आधार पर राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल ने 24 राज्यों एवं चार केंद्रशासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है. ट्रिब्यूनल ने रेखांकित किया है कि इन धातुओं या रसायनों की मात्रा मिलना एक बेहद गंभीर मामला है और इनसे बचाव के उपाय तुरंत किये जाने चाहिए. ऐसी समस्याओं के अध्ययन और समाधान में कुछ अजीब पेंच हैं. उदाहरण के लिए, भूजल का नियमन करना केंद्रीय भूजल प्राधिकरण की जिम्मेदारी है, पर ट्रिब्यूनल ने पाया कि इस अथॉरिटी ने इस आधार पर कोई स्वतंत्र पहल नहीं की क्योंकि जल राज्य का विषय है. पर प्राधिकरण के इस तर्क को 1997 में सर्वोच्च न्यायालय और 2022 में हरित ट्रिब्यूनल द्वारा खारिज किया जा चुका है. अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बचने की कोशिश पर ट्रिब्यूनल ने भूजल प्राधिकरण को फटकार भी लगायी है. इस मामले में राज्यों के साथ-साथ भूजल प्राधिकरण और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी पक्ष बनाया गया है. जिन राज्यों को नोटिस दिया गया है, उनमें बिहार, झारखंड और बंगाल भी शामिल हैं. अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी. उल्लेखनीय है कि वायु प्रदूषण के मामले में भी कई राज्यों का रवैया निराशाजनक रहा है. बहुत से राज्य अपने यहां प्रदूषण की स्थिति और समाधान के प्रयास के बारे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित जानकारी नहीं भेजते. अनेक बार तो अदालती आदेशों की भी परवाह नहीं की जाती. हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नल से जल पहुंचाने तथा संक्रामक रोगों से बचाव के लिए ठोस उपाय हो रहे हैं, पर देश के बड़े हिस्से में भूजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है. लोग कई बार जानकारी के अभाव में या मजबूरी में घातक रसायनों वाले पानी को उपयोग में लाते हैं. इसलिए जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है. भूजल प्रकृति द्वारा दी गयी अमूल्य निधि है. उसका संरक्षण भी हमारी प्राथमिकताओं में होना चाहिए. देश के अनेक हिस्सों में भूजल का इतना दोहन हुआ है कि जल स्तर बहुत नीचे चला गया है. वर्षा जल ठीक से जमा नहीं होने और लगातार दोहन से रिचार्ज प्रक्रिया पर असर पड़ता है. आशा है कि केंद्र और राज्य सरकारें अपनी जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य नीति में भूजल प्रबंधन को समुचित स्थान देंगी.

GST कलेक्शन और UPI पेमेंट में उछाल, कारों की रेकॉर्ड सेल...

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय इकॉनमी के लिए नए साल का पहला दिन ढेर सारी खुशियां लेकर आया। साल के पहले दिन शेयर बाजार रेकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले नौ महीने में एवरेज मंथली जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल के मुकाबले 12 फीसदी अधिक है। देश में पिछले साल कारों की बिक्री 40 लाख रुपये के पार पहुंच गई। दिसंबर में यूपीआई पेमेंट में 42 फीसदी की तेजी आई, एनबीएफसी को लोन नवंबर में 22 परसेंट उछल गया और दिसंबर में एफपीआई ने भारत के डेट मार्केट में 18,000 करोड़ रुपये झोंके जो 77 महीने में सबसे अधिक है।

जीएसटी कलेक्शन

जीएसटी कलेक्शन दिसंबर में पिछले साल के मुकाबले 10ऽ बढ़कर लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही अप्रैल-दिसंबर, 2023 की अवधि में जीएसटी कलेक्शन 12 प्रतिशत की मजबूत ग्रोथ के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले साल के शुरुआती नौ महीनों में यह 13.40 लाख करोड़ रुपये रहा था। दिसंबर इस फाइनेंशियल ईयर का सातवां महीना है जिसमें 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी संग्रह हुआ है।

यूपीआई पेमेंट

दिसंबर में यूपीआई ट्रांजैक्शन की वैल्यू पिछले साल के मुकाबले 42 परसेंट बढ़कर 18 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई जबकि वॉल्यूम 54 परसेंट बढ़कर 1,202 करोड़ रहा। पिछले महीने की तुलना में इसके वॉल्यूम में सात फीसदी तेजी आई है। दिसंबर में यूपीआई के तहत एवरेज डेली ट्रांजैक्शन 40 करोड़ पहुंच गया है। एनपीसीआई ने तीन साल में इसे 100 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

फास्टैग ट्रांजैक्शन

दिसंबर में फास्टैग ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम पिछले साल के मुकाबले 13ऽ उछलकर 34.8 करोड़ पहुंच गया। इस दौरान ट्रांजैक्शन की वैल्यू 19 परसेंट उछलकर 5,861 करोड़ रुपये पहुंच गई। यह नवंबर के मुकाबले 10 फीसदी अधिक है। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों से यात्रा की जिससे फास्टैग के वॉल्यूम और वैल्यू में तेजी आई।

रेकॉर्ड गाड़ियां बिकीं

2023 में पहली बार देश में गाड़ियों की बिक्री का आंकड़ा 40 लाख के पार पहुंच गया। यह पिछले साल के मुकाबले 8.4 फीसदी ज्यादा है। इंडस्ट्री के मुताबिक पिछले साल 41.1 लाख गाड़ियां बिकीं जबकि 2022 में यह आंकड़ा 37.9 लाख यूनिट था। देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी ने पिछले साल 20 लाख गाड़ियां बेचीं। इसी तरह हुंडई की घरेलू बिक्री भी छह लाख यूनिट को पार कर गई है।

एनबीएफसी को लोन

नवंबर में एनबीएफसी कंपनियों के लिए बैंक लोन 22 फीसदी की तेजी के साथ करीब 15 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में बैंकों का होम लोन 25.9 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। इस दौरान पर्सनल लोन में पिछले साल के मुकाबले 30 फीसदी तेजी आई है। इसी तरह क्रेडिट कार्ड का बकाया भी 2.5 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।

शेयर बाजार रेकॉर्ड पर

साल के पहले दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुले लेकिन दिन खत्म होते-होते मामला पलट गया। बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स करीब 32 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ जबकि निफ्टी 21,750 अंक के करीब पहुंच गया। कारोबार के दौरान दोनों इंडेक्सेज ने नया रेकॉर्ड छुआ। सेंसेक्स 72,562 अंक और निफ्टी 21,834 अंक पर पहुंचा।

विदेशी निवेश

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने दिसंबर में भारत के डेट मार्केट में 18,000 करोड़ रुपये से ज्यादा निवेश किया जो जुलाई 2017 के बाद सबसे अधिक है। दिसंबर में एफपीआई इनफ्लो 18,393 करोड़ रुपये रहा जो नवंबर में 14,106 करोड़ रुपये था। जानकारों का कहना है कि कैलेंडर ईयर 2024 की पहली तिमाही में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है।

रुपया शुरुआती कारोबार में चार पैसे की बढ़त के साथ 83.28 प्रति डॉलर पर

मुंबई। एजेंसी

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के रुख के बीच बुधवार को रुपया शुरुआती कारोबार में चार पैसे की बढ़त के साथ 83.28 प्रति डॉलर पर मजबूत खुला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि स्थानीय शेयर बाजारों में नकारात्मक रुख की वजह से भारतीय मुद्रा पर दबाव

बना हुआ है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 83.30 प्रति डॉलर पर खुला और बाद में 83.28 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। यह पिछले बंद भाव से चार पैसे की बढ़त है। रुपया मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83.32 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह अन्य मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी मुद्रा की मजबूती का आकलन करने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 102.08 पर कारोबार कर रहा था। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.09 प्रतिशत के नुकसान के साथ 75.87 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने मंगलवार को 1,602.16 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

नए साल के साथ 8 नियम भी बदल गए

आपकी जेब पर ऐसे बढ़ेगा बोझ

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

नए साल 2024 का आगाज हो गया है। देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बड़े बदलाव होते हैं। जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होता है। नए साल के पहले ही दिन सरकार ने आम जनता को खुशखबरी दी है। नए साल के पहले दिन कमर्शियल गैस के दाम कम हुए हैं। इसके अलावा आज से कौन से नियम बदलने वाले हैं, इनकी जानकारी होना जरूरी है।

नए सिम कार्ड नियम

1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने और रखने के नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सिम कार्ड खरीदने पर सिर्फ डिजिटल ख्ण ही होगी। इससे पहले डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता था।

UPI ID हो गई डीएक्टिवेट

नए साल से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई (NPCI) नई पॉलिसी लागू कर रहा है। इसके तहत एक या उससे ज्यादा साल से इनएक्टिविट यूपीआई आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा।

1 जनवरी को एलपीजी के रेट

आईओसीएल ने देश के लोगों को नए साल का तोहफा दिया है।19 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत में एक महीने में दूसरी बार गिरावट देखने को मिली है. वैसे दाम में मामूली गिरावट है। अगर इसे पूरे महीने के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कीमत में 39 रुपए से लेकर 44 रुपए तक की गिरावट आई है।

म्युचुअल फंड और डीमैट अकाउंट वालों को बड़ी राहत

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्युचुअल फंड और डीमैट खाता में नॉमिनेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले नॉमिनी बताने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी।अब 6 महीने का समय और दे दिया गया है. अब नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 30 जून, 2024 कर दी गई है।

बंद हो सकता है जीमेल अकाउंट

अगर आपने अपने जीमेल अकाउंट को 1-2 साल से इस्तेमाल नहीं किया है तो आपका गूगल का जीमेल अकाउंट बंद हो सकता है। गूगल का ये नियम सिर्फ पर्सनल अकाउंट पर होगा। ये नियम बिजनेस अकाउंट पर लागू नहीं होगा।

इनकम टैक्स डेडलाइन

असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी डेट 31 दिसंबर को खत्म हो गई है। इसके बाद आपको इस साल के लिए आईटीआर दाखिल करने का मौका नहीं मिलेगा।

बैंक लॉकर एग्रीमेंट

बैंक के नए लॉकर एग्रीमेंट को साइन करने की डेडलाइन खत्म हो रही है। इसके बाद बाद जब तक आप नया लॉकर एग्रीमेंट साइन नहीं करते हैं, तब तक आपको लॉकर ऑपरेट करने की सुविधा नहीं मिलेगी।

रू. 2000 के नोट को लेकर आया RBI से अपडेट

मार्केट से वापस नहीं आए इतने नोट

नई दिल्ली। एजेंसी

भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि 29 दिसंबर को कारोबार बंद होने पर बैंक से बाहर 2,000 रूपए के बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर 9,330 करोड़ रूपए रह गया। इस तरह 2000 रुपए के 97.38 प्रतिशत बैंक नोट अब बैंकों में वापस आ गए हैं और अब सिर्फ 9,330 करोड़ रुपये के नोट ही लोगों के पास बचे हैं। 19 मई, 2023 को कारोबार बंद होने पर प्रचलन में 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था, जब इसे बैंकों में जमा करने की घोषणा की गई थी।

आरबीआई ने बयान में कहा, '2,000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य, जो 19 मई, 2023 को कारोबार समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपये था, अब 29 दिसंबर, 2023 को कारोबार बंद होने के समय घटकर 9,330 करोड़ रुपये हो गया है।'

19 जगहों पर बदले जा सकते हैं नोट

केंद्रीय बैंक ने कहा कि 2,000 रुपये के नोट अब भी वैध मुद्रा बने हुए हैं। इन नोटों को आरबीआई के देशभर में मौजूद 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर बदला या जमा किया जा सकता है। इसके अलावा लोग किसी भी डाकघर से आरबीआई के किसी भी कार्यालय में इंडिया पोस्ट के माध्यम से 2,000 रुपये के नोट अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए भेज सकते हैं।

RBI ऑफिस के बाहर लगी भीड़

आरबीआई ने इन नोटों को चलन से वापस लेते समय इन नोटों को 30 सितंबर तक बदलने या बैंक खातों में जमा करने के लिए कहा था। बाद में समयसीमा को सात अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। आठ अक्टूबर से लोग आरबीआई के 19 कार्यालयों में जाकर 2,000 रुपये के नोटों को बदल या जमा करा सकते हैं।इस वजह से इन कार्यालयों में कामकाजी घंटों के दौरान अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिल रही है।

2016 में जारी हुआ था 2000 रुपये का नोट

आरबीआई के ये कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं। नवंबर, 2016 में 1,000 रुपये और 500 रुपये के तत्कालीन नोटों का चलन बंद करने के बाद आरबीआई ने 2,000 रुपये का नोट जारी किया था।

राम मंदिर उद्घाटन से इकॉनमी को मिलेगा दम

50,000 करोड़ का कारोबार होने का अनुमान

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

अयोध्या में भगवान राम का विशाल मंदिर बन रहा है। इसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को होना है। इसके लिए देशभर में जोरदार तैयारियां चल रही हैं। बड़ी संख्या में रामभक्तों के अयोध्या पहुंचने का अनुमान है। साथ ही इस मौके को यादगार बनाने के लिए पूरे देश में शानदार तैयारियां की जा रही हैं। इसे बिजनस के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर देशभर में 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। कारोबारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के मुताबिक 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन देशभर में 50,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यापार होने का अनुमान है। इसके लिए कारोबारियों ने अभी से कमर कस ली है। इस मौके के भव्य बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि विश्व

हिंदू परिषद के आह्वान पर देशभर में श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर एक जनवरी से अभियान चलाने की घोषणा की गई है। इससे देशभर के लोगों में उत्साह दिख रहा है। इसमें बिजनस का भी बड़ा अवसर दिख रहा है। उम्मीद है कि जनवरी में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार होगा।

किन चीजों की है डिमांड

खंडेलवाल ने बताया कि देश के सभी बाजारों में भगवान राम से जुड़ी चीजों की भारी मांग देखी जा रही है। इनमें श्री राम ध्वजा, श्री राम अंगवस्त्र सहित श्री राम के चित्र से अंकित मालाएं, लॉकेट, चाबी की रिंग, राम दरबार के चित्र, राम मंदिर के मॉडल के चित्र, सजावटी लटकनें और कड़े सहित अनेक प्रकार का सामान शामिल है। साथ ही श्री राम मंदिर के मॉडल की भी भारी मांग है। इसे हार्डबोर्ड, पाइनवुड और लकड़ी से अलग-अलग साइज में तैयार किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में महिलाओं और स्थानीय कारीगरों को रोजगार मिल रहा है। साथ ही कुर्ते, टी-शर्ट एवं दूसरे कपड़ों पर श्री राम मंदिर के मॉडल की हाथ से कढ़ाई या फिर छपाई हो रही है। कुर्ते बनाने में खादी का उपयोग किया जा रहा है। 22 जनवरी को देशभर में दिवाली मनाने का आह्वान किया गया है। इससे मिट्टी के दिये, रंगोली बनाने के सामान, फूल, बाजारों एवं घरों में रोशनी के लिए बिजली के सामान की भारी मांग है। इससे बिजनस में तेजी आएगी। साथ ही बड़ी संख्या में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, पत्रक और स्टीकर बगैरह तैयार किए जा रहे हैं। इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है।

हाथ से फिसल रही इकॉनमी...

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी आखिर मान लिया

नई दिल्ली। एजेंसी

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी चीन पिछले कुछ समय से आर्थिक मोर्चे पर दिक्कतों का सामना कर रही है। लेकिन वहां की सरकार इसे मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी मान लिया है कि उनके देश में सबकुछ ठीक नहीं है। नए साल की पूर्व संध्या पर उन्होंने कहा कि देश में कंपनियों को संघर्ष करना पड़ रहा है और लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। यह पहला मौका है जब चीनी राष्ट्रपति ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है।

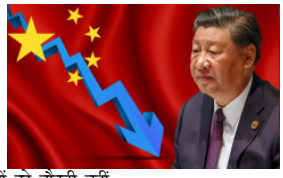

चीन की इकॉनमी कमजोर मांग, बढ़ती बेरोजगारी और रियल एस्टेट संकट से जूझ रही है। विदेशी कंपनियां और निवेशक भी उससे मुंह मोड़ रहे हैं। शी ने कहा कि कुछ कंपनियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों को नौकरी मिलने और अपना गुजारा करने में मुश्किल हो रही है। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि ये सब बातें उनके ध्यान में हैं और सरकार इकनॉमिक रिकवरी को तेज करने की दिशा में काम करेगी। शी के भाषण से कुछ घंटे पहले नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पीएमआई सर्वे जारी किया। इसके मुताबिक देश में फैक्ट्री एक्टिविटी दिसंबर में गिरकर छह महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। पिछले महीने आधिकारिक मैन्यूफैक्चरिंग पीएमआई 49 पर आ गया जो नवंबर में 49.4 था। 50 से ऊपर इसका विस्तार माना जाता है जबकि उससे नीचे गिरावट मानी जाती है। दिसंबर में लगातार तीसरे महीने इसमें गिरावट आई है।

इकॉनमी पर संकट

चीन की इकॉनमी को इस साल कई तरह की दिक्कतों के सामना करना पड़ रहा है। देश का रियल एस्टेट सेक्टर गंभीर संकट से जूझ रहा है। देश की इकॉनमी में इसकी एक तिहाई हिस्सेदारी है। धीरे-धीरे इसने दूसरे सेक्टर्स को भी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। साथ ही देश में बेरोजगारी दर चरम पर है, डिफ्लेशन की स्थिति है और स्थानीय सरकारों पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने ग्रोथ और रोजगार को पटरी पर लाने के लिए कई उपाय किए हैं लेकिन अब तक उनका कोई नतीजा नहीं दिखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर विदेशी कंपनियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इस कारण कई कंपनियों ने चीन से बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। अमेरिका के साथ तनाव भी चरम पर है। पिछले साल दुनिया के अधिकांश देशों में शेयर बाजारों में तेजी रही लेकिन चीन में गिरावट आई।

तो इस बार वेतनभोगी को मोहेंगी निर्मला सीतारमण?

बात बजट 2024 की

नई दिल्ली। एजेंसी

इस साल का का बजट मतलब कि बजट 2024 (ँलु 2024) का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अभी से पहले के बजट में तो वेतनभोगी टैक्सपेयर्स (घ्हम्दस ऊँ ईंबे) ठगे ही गए हैं। लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उन्हें राहत मिलेगी। वित्त मंत्रालय से जुड़े आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि साल 2024 के बजट में कुछ खास हो सकता है। आइए जानते हैं क्या हो सकता है बजट में

आम चुनाव से पहले का है बजट

बजट 2024 आम चुनाव से ठीक पहले का बजट है। इसलिए यह पूर्ण बजट नहीं होगा बल्कि वोट ऑन अकाउंट (Vote on Account) होगा। यह कुछ महीने के लिए होगा। इसके बाद जो सरकार चुन कर आएगी, वही नया बजट संसद में पेश करेगी। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार आत्मविश्वास में है, उसे देख कर लगता है कि इस बार के वोट ऑन अकाउंट में भी काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। नार्थ ब्लॉक के गलियारों से जो छन-छन कर खबर आ रही है, उससे तो यही संकेत है कि बजट 2024 में 10 लाख रुपए तक की सैलरी वालों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।

क्या बदलेगा इनकम टैक्स स्लैब?

सीबीडीटी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए बजट में इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab) में चेंज किया जा सकता है। हालांकि, इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। लेकिन किसी सैलरी वर्ग वालों को कुछ छूट संभव है। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो मौजूदा सिस्टम में इनकम टैक्स के कुल 5 स्लैब हैं। इनमें 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कैटेगरी में आती है। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स है। वहीं, 5 लाख से 10 लाख की आय पर सीधे 20 फीसदी टैक्स चुकाना होता है। 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगता है और 20 लाख से ऊपर की इनकम वालों को भी 30 फीसदी टैक्स चुकाना होता है। वहीं, न्यू टैक्स रिजीम में अभी तक 7 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री के दायरे में आती है। इसमें और बड़ी छूट दी जा सकती है। इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। बताया जाता है कि वित्त मंत्री ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं करेंगी। जो कुछ होगा, न्यू टैक्स रिजीम में ही होगा।

फोकस क्या रहेगा

वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो बजट में 10 लाख रुपए तक की सैलरी वाला स्ट्रक्चर फोकस में होगा। इसमें बदलाव की संभावना है। अभी 10 लाख तक की सैलरी दो टैक्स स्लैब में आती है। पहला 6 से 9 लाख रुपए, जिस पर 10 फीसदी टैक्स है। वहीं, 9 लाख से 12 लाख जिस पर 15 फीसदी टैक्स है। ऐसे में दो टैक्स स्लैब को सीधे 10 लाख का स्लैब बनाने की कोशिश हो सकती है। इस पर भी 10 फीसदी टैक्स लगाने की ही योजना है. इसमें 6-9 लाख रुपए वाला स्लैब बदला जा सकता है। इन बातों के अलावा कुछ और प्रावधान किया जा सकता है।

ज्यादा आमदनी वालों के लिए क्या

मौजूदा टैक्स सिस्टम में न्यू रिजीम में 15 लाख रुपए की आय वालों पर 20 फीसदी टैक्स लगता है। मतलब अगर 10 लाख तक देखें तो 10 और 15 फीसदी की दर से टैक्स लगता है। वहीं, 15 लाख पर 20 फीसदी टैक्स है। ऐसी संभावना है कि 15 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया जाए। 10 लाख तक सीधे 10 फीसदी और 10 से 15 लाख रुपए की इनकम पर सीधे 20 फीसदी टैक्स लगाया जाए। ऐसी स्थिति में 10 से 12 फीसदी स्लैब में आने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा लेकिन, 10 लाख तक काफी बड़ी राहत मिल जाएगी।

लगातार सातवें महीने जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ के पार

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

जीएसटी कलेक्शन दिसंबर में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़कर लगभग 1.64 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक साल पहले की समान अवधि में जीएसटी संग्रह 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा था। मंत्रालय ने बयान में कहा कि इसके साथ ही अप्रैल-दिसंबर, 2023 की अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 12 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि के साथ 14.97 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। पिछले साल की समान अवधि में इन नौ महीनों में कर संग्रह 13.40 लाख करोड़ रुपये रहा था।

इस तरह वित्त वर्ष 2023-24 के पहले नौ महीने की अवधि में औसत मासिक कर संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की समान अवधि में दर्ज 1.49 लाख करोड़ रुपये के औसत कर संग्रह से 12 प्रतिशत अधिक है। मंत्रालय ने बयान में कहा, 'दिसंबर में एकत्रित सकल जीएसटी राजस्व 1,64,882 करोड़ रुपये है, जिसमें से सीजीएसटी 30,443 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 37,935 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 84,255 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 41,534 करोड़ रुपये सहित) है। इसके अलावा उपकर के रूप में 12,249 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 1,079 करोड़ रुपये सहित) का संग्रह हुआ है।'

लगातार बढ़ रहा कलेक्शन

खास बात यह है कि दिसंबर इस साल का सातवां महीना है जिसमें 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का जीएसटी संग्रह हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में मासिक जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हुई है। यह 2017-18 में प्रति माह औसतन एक लाख करोड़ रुपये से कम था। महामारी से प्रभावित 2020-21 के बाद कलेक्शन तेजी से बढ़कर 2022-23 में औसतन 1.51 लाख करोड़ रुपये हो गया। बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के कारण और अधिक कुशल कर प्रशासन के चलते भी कलेक्शन बढ़ रहा है।

मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम का क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन में प्रारंभ हुआ

कार्यकारी संचालक श्री राजेश राठौड़ द्वारा पदभार ग्रहण

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा गत दिवस औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निवेश प्रोत्साहन एवं औद्योगिक विकास हेतु वर्तमान में कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा के अतिरिक्त अन्य संभागीय मुख्यालयों पर भी क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ करने तथा उज्जैन संभाग हेतु तत्काल क्षेत्रीय कार्यालय प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों पर अमल करते हुए उज्जैन संभाग हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड में प्रारंभ किया जाकर कार्यकारी संचालक मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम इंदौर श्री राजेश राठौड द्वारा आज क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन संभाग के कार्यकारी संचालक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों के अनुपालन में प्रारंभ उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय से उज्जैन संभाग के उद्योगपतियों की स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं एवं समस्याओं का समाधान संभव हो सकेगा। इससे उज्जैन संभाग में उद्योगों की स्थापना एवं रोजगार सृजन में तेजी आएगी। संभाग के उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्णय की प्रशंसा करते हुए उज्जैन संभाग के औद्योगिकीकरण में इस पहल को अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय बताया है।

इकॉनमी को नहीं आने देंगे कोई आंच

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया पूरा प्लान

नई दिल्ली। एजेंसी

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा कि सेंट्रल बैंक देश की अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले किसी भी रिस्क से निपटने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत ग्रोथ की बढ़ती संभावनाओं के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। RBI गवर्नर ने कहा कि रिटेल कर्ज के कुछ सेगमेंट के प्रति बैंकों के 'उत्साह' को रोकने के लिए सेंट्रल बैंक ने हाल में कदम उठाए हैं। दास ने कहा कि ग्लोबल इकॉनमी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। इनके बीच भारत की अर्थव्यवस्था एक मजबूत फाइनैंशल सिस्टम के साथ मेक्रो-इकॉनमिक मोर्चे पर मजबूती दिखा रही है। उन्होंने कहा, 'हम किसी भी रिस्क को बढ़ने से रोकने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई करने को लेकर सतर्क और प्रतिबद्ध हैं।' RBI गवर्नर ने यह भी कहा कि खुदरा कर्ज के कुछ खंडों के प्रति बैंकों के 'उत्साह' को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक ने हाल में कदम उठाए है। यह अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतों के लिए कोष की उपलब्धता से समझौता किए बिना वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की उसकी प्रतिबद्धता को बताता है। उन्होंने कहा, 'भारत ग्रोथ की बढ़ती संभावनाओं के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैष्ठ। वृद्धि में तेज उछाल, मजबूत आर्थिक बुनियाद, मजबूत घरेलू मांग और सार्वजनिक नीतियों के स्तर पर सूझबूझ का नतीजा है।' RBI की फाइनेंशियल स्टैबिलिटी रिपोर्ट (इएँ) 2022-23 में कहा गया है कि बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग असेट (ऊँ) रेशयो सितंबर, 2023 में घटकर कई साल के निचले स्तर 3.2 प्रतिशत और शुद्ध ऊँ अनुपात 0.8 प्रतिशत पर रहा है। इस अवधि में बैंकों का ग्रॉस नॉन परफॉर्मेंस असेट (GNPA) रेशयो भी घटकर कई साल के निचले स्तर 3.2 प्रतिशत पर आ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्थिति मजबूत हुई है, ग्रॉस NPA सितंबर 2023 तक 4.6 प्रतिशत और संपत्ति पर रिटर्न 2.9 प्रतिशत रहा है।

क्या इंडिया में फिर सजेगी क्रिप्टोकरंसी की महफिल?

नई दिल्ली। एजेंसी

क्रिप्टोकरंसी को लेकर भारत में जो उफान एक समय आया था, वह टैक्स नियमों के चलते ठंडा पड़ गया। इसके चलते भारत के क्रिप्टो एक्सचेंज भी मुश्किल में पड़ गए। हालांकि उनका कहना है कि तस्वीर अब बदल सकती है। फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट ने नौ विदेशी वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिस जारी किया है। यह कारण बताओ नोटिस नियमों के पालन के संबंध में जारी किया गया। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी मिनिस्ट्री से अनुरोध किया गया है कि जो विदेशी सर्विस प्रोवाइडर नियमों का पालन न करें, उनका यूआरएल ब्लॉक कर दिया जाए। इंडिया के क्रिप्टो एक्सचेंजों का कहना है कि इससे नियमों के मामले में विदेशी और देसी एक्सचेंजों के बीच का फर्क खत्म होगा। उनका कहना है कि इस कदम से इंडियन एक्सचेंजों का कारोबार बढ़ सकता है क्योंकि कई निवेशक टैक्स बचाने के लिए ग्लोबल एक्सचेंजों पर ट्रेड कर रहे थे। अब वे फिर से देसी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर आ सकते हैं।

डिजिटल एसेट एक्सचेंज बाययूकॉइन (BuyUcoin) के सीईओ शिवम ठकराल कहते हैं, 'सबसे बड़ा असर विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर होगा। काफी ट्रेडिंग वॉल्यूम

इंडियन एक्सचेंजों पर शिफ्ट हो सकता है जो फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट के नियमों का पालन कर रहे हैं।'

2022 के आम बजट में क्रिप्टो ट्रेडिंग से होने वाले लाभ पर 30 प्रतिशत टैक्स लगा दिया गया था। इसके साथ ही 1 पर्सेंट का टीडीएस लागू किया गया। लॉस ऑफसेट करने की गुंजाइश भी नहीं रही। नई दिल्ली के टेक्नॉलजी पॉलिसी थिंक टैंक ँ ँ णहीा की एक स्टडी के मुताबिक, इसके चलते भारत के सेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम तेजी से घटा। फरवरी से मार्च 2022 के बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम 95 प्रतिशत से ज्यादा घट गया था। स्टडी के मुताबिक, फरवरी से अक्टूबर 2022 के बीच 3.85 अरब डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम देसी एक्सचेंजों से विदेशी एक्सचेंजों पर शिफ्ट हो गया था।

पिछले डेढ़ वर्षों से भारतीय क्रिप्टो निवेशक ग्लोबल एक्सचेंजों की ओर जा रहे हैं। 9 विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के यूआरएल ब्लॉक हो सकने की खबर आने के बाद ये निवेशक काफी परेशान हैं। ये ऐसे विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग पर एक प्रतिशत टीडीएस की शर्त भी पूरी नहीं कर रहे।

नोएडा बेस्ड ट्रेडर और पॉपुलर इंफ्लुएंसर विशाल गुप्ता कहते हैं, 'निवेशकों का काफी पैसा ग्लोबल एक्सचेंजों पर है। निवेशक अब वहां से पैसा निकालने के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। कुछ तो अपने हॉर्डवेयर वॉलेट्स या थर्ड पार्टी वॉलेट्स में एसेट्स ट्रांसफर भी करने लगे हैं।' गुप्ता का कहना है कि परेशान निवेशकों की ओर से उनके पास काफी सवाल आ रहे हैं।

इस इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का कहना है कि भारत के क्रिप्टो निवेशकों के बीच तीन विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज बहुत पॉपुलर हैं। इनके नाम हैं ध्र्ढ्ढ, ँ ँ ू और ँ ू ठ्ठ। फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट की लिस्ट में इनके नाम शामिल नहीं हैं। वहीं, कुछ ऐसे एक्सचेंज इस लिस्ट में हैं, जिन्होंने या तो अपने नाम बदल लिए हैं या वे पॉपुलर नहीं हैं। एक इंडियन एक्सचेंज के सीईओ ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर कहा, 'यह पुरानी लिस्ट है, जिसे सरकार ने इस केस में यूज किया है। कुछ पॉपुलर लेकिन केवाईसी नियमों का पालन नहीं करने वाले एक्सचेंज इस लिस्ट में हैं ही नहीं।'

हालांकि इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री का मानना है कि फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट के इस कदम से निवेशकों की बेहतर तरीके से सुरक्षा हो सकेगी। कॉइनडीसीएक्स (एदग्हअ्रें) के को-फाउंडर सुमित गुप्ता ने कहा, 'पुख्ता रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से ट्रांसपैरेंसी रहती है, कंज्यूमर्स की सुरक्षा होती है और फाइनैंशल क्राइम से निपटने में मदद मिलती है। इस कदम से रिस्क घटाने के साथ यूजर्स और इनवेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने में मदद मिलेगी।' उन्होंने कहा कि भारत के अधिकतर वर्चुअल डिजिटल एसेट एक्सचेंज मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के नियमों का पालन करते हैं।

मार्च 2023 में वीडीए को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के दायरे में लाया गया था। भारत में वीडीए सर्विसेज देने वाले किसी भी एक्सचेंज को इस एक्ट का पालन करना होता है, चाहे वह भारतीय इकाई हो या न हो।

कॉइनडीसीएक्स, कॉइनस्विच और वजीरएक्स सहित कुल 28 वीडीए एक्सचेंजों ने फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली है। अभी नौ विदेशी एक्सचेंजों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है।

वजीरएक्स (WazirX) के वाइसा प्रेसिडेंट राजागोपाल मेनन का कहना है, 'ऐसा लग रहा है कि ये विदेशी एक्सचेंज इंडिया की लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसियों की बात नहीं मान रहे हैं। इनसे डेटा मांगा जा रहा है, ये नहीं दे रहे हैं। यह नोटिस साफ कर देता है कि इन्हें फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जब जरूरी होगा डेटा शेयर करना होगा। अगला कदम यह हो सकता है कि इन विदेशी एक्सचेंजों से यह कहा जाए कि भारत में रह रहे भारतीयों को वे जो सेवाएं देते हैं, उनके लिए वे भारत के टीडीएस कानूनों का पालन करें।'

हालांकि इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का कहना है कि अधिकतर ग्लोबल एक्सचेंजों के लिए पीएमएलए की सख्त गाइडलाइंस का पालन करना मुश्किल होगा। इससे इन एक्सचेंजों पर माइग्रेट कर चुके भारतीय निवेशकों के लिए परेशानी बढ़ेगी।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत के क्रिप्टो निवेशकों को अपनी एसेट्स ऐसे एक्सचेंज पर रखनी चाहिए, जो रेगुलेटेड हो और फाइनैंशल इंटेलिजेंस यूनिट के नियमों का पालन करता हो। उनका यह भी कहना है कि सरकार को यूजर्स को समय देना चाहिए ताकि वे अपनी एसेट्स विदेशी एक्सचेंजों से हटा सकें। बाययूकॉइन के ठकराल ने कहा, 'सरकार को विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के यूआरएल ब्लॉक करने में नपेतुले ढंग से कदम बढ़ाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि काफी इंडियन ट्रेडर्स ने अपनी एसेट्स ऐसे एक्सचेंजों पर रखी हो।'

तूफानी तेजी से भाग रही भारत की अर्थव्यवस्था

रेटिंग एजेंसियां भी मान रहीं लोहा, नए साल पर आई गुड न्यूज

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इसका लोहा रेटिंग एजेंसियां भी मान रही हैं। नए साल में भारत के लिए अब एक और अच्छी खबर आई है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि अनुमान को 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 फीसदी कर दिया है। एजेंसी ने इसके लिए मजबूत अर्थव्यवस्था, लगातार हो रहे विकास और एक नए निजी कॉरपोरेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की संभावना का हवाला दिया है। रेटिंग एजेंसी ने वृद्धि अनुमान को प्रभावित करने वाले जोखिमों के रूप में ग्लोबल लेवल पर अस्थिर स्थिति के अलावा, कमजोर वैश्विक वृद्धि और कारोबार को चिह्नित किया है।

दूसरी तिमाही में इतनी रही जीडीपी

इंडिया रेटिंग्स के प्रमुख अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा, 'ये सभी जोखिम चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि को 6.7 फीसदी तक सीमित रखेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि सालाना 7.8 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत रही है। इसके चालू वित्त वर्ष की शेष दो तिमाहियों में धीमी होने की संभावना है।' भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को भी शेष दो तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि कुछ सुस्त पड़ने की आशंका है। केंद्रीय बैंक ने संभावना जताई है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत पर रहेगी।

रेटिंग एजेंसी ने कही ये बात

पिछले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रही थी। इंडिया रेटिंग्स ने बयान में कहा कि उसने चालू वित्त वर्ष के लिए देश के जीडीपी वृद्धि अनुमान को पूर्ववर्ती 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। इसके पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, निरंतर सरकारी पूंजीगत व्यय, कॉरपोरेट्स/बैंकिंग क्षेत्र में घटता कर्ज, एक नए निजी कॉरपोरेट पूंजीगत व्यय चक्र की संभावना और शेष विश्व से धन प्रेषण के साथ व्यापार और सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में निरंतर गति बनी रहने जैसे कई कारक हैं। इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि उपभोक्ता मांग व्यापक आधार वाली नहीं है। उपभोग वृद्धि के लिए वेतन वृद्धि महत्वपूर्ण है। इंडिया रेटिंग्स की गणना से पता चलता है कि वास्तविक मजदूरी में एक प्रतिशत की वृद्धि से वास्तविक निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में 1.12 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है और इसके गुणक प्रभाव से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 0.64 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

सुकन्या सहित छोटी बचत योजनाओं पर बढ़ाया ब्याज

सरकार ने किया नई दरें का ऐलान

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने नए साल पर बड़ा तोहफा दिया है। नए साल में सरकार ने छोटी बचत योजनाओं (Small Savings Scheme Interest Rate) से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) तक की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। सरकारी घोषणा के मुताबिक 3 साल की सेविंग स्कीम पर ब्याज दर 0.1 फीसदी बढ़ा दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) पर ब्याज दर 0.2इ बढ़ाई गई है। जनवरी-मार्च की तिमाही में अब सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2 फीसदी ब्याज मिलेगा। सरकार हर तीन महीने में इ्इ, एएभ, एएएए और ख्ख्र जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरें तय करती है। सरकार की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने से अब नए साल पर लोगों को निवेश पर ज्यादा फायदा मिलेगा।

सुकन्या समृद्धि की नई दरें

वित्त मंत्रालय की ओर से अब जनवरी से मार्च 2024 तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दर को 8 फीसदी से बढ़ाकर अब 8.20 फीसदी कर दिया गया है। इस योजना में बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक माता-पिता या कानूनी अभिभावक बिटिया का खाता खोल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता पोस्ट ऑफिस और बैंकों में खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि स्कीम के तहत न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये सालाना और अधिकतम 1,50,000 रुपये सालाना है। इससे पहले सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही के लिए ब्याज दरों को नहीं बढ़ाया था। अगर एक कारोबारी साल में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये डिपॉजिट नहीं होती है तो डिफॉल्ट होने पर हर साल 50 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें

सरकारी घोषणा के मुताबिक, तीन साल की सेविंग स्कीम पर ही ब्याज दरों को बढ़ाया गया है। 3 साल की सेविंग स्कीम पर ब्याज दर 0.1 फीसदी बढ़ा दी गई है। अब इसमें 7.1 फीसदी ब्याज मिलेगा। एक साल की सेविंग स्कीम पर 4 फीसदी, दो साल की सेविंग पर 6.9 फीसदी, 5 साल की सेविंग पर 7.5 फीसदी का ब्याज मिलेगा। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अर्थव्यवस्था के मामले में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। पिछले साल के 5.7 फीसदी विकास दर की तुलना में इस साल इकोनॉमी के 8 सेक्टरों में 7.8 प्रतिशत की ग्रोथ रेट दर्ज की गई है।

यूरोप को पीछे छोड़ भारत बना एडवांस, अब नहीं है ब्रिटेन-फ्रांस के पास कोई चांस

नई दिल्ली। एजेंसी

बीते 3 दशक में भारत ने गजब दौर देखा है। इस दौरान देश ने नरसिम्हा राव के 'उदारीकरण', अटल बिहारी वाजपेयी के 'शाइनिंग इंडिया' और फिर मनमोहन सिंह के 'भारत निर्माण' को देखा। अब बीते 10 साल के दौरान देश ने पिछले 30 सालों का सबसे मजबूत नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में देखा। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को दुनिया सिर्फ देख ही नहीं रही, बल्कि उससे हैरान भी है। आखिर आज भारत 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के मुहाने पर कैसे पहुंच गया है? सरकार को भरोसा है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। साल 2047 तक यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा।

बीते 3 दशकों में भारत ने इकोनॉमिक मोर्चे पर यूरोप की आर्थिक महाशक्तियों को पीछे छोड़ा है, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये दो महाशक्तियां फ्रांस और ब्रिटेन हैं। करीब 31 साल पहले जो ग्लोबल इकोनॉमी की तस्वीर थी, वो अब कुछेक जगहों को छोड़कर पूरी तरह से बदल चुकी है। भारत अब फ्रांस और ब्रिटेन से इतना आगे निकल चुका है कि अब इन दोनों देशों का भारत की इकोनॉमी को ओवरटेक करने का कोई चांस ही नहीं है। आइए इन तीन दशकों को भारत, ब्रिटेन और फ्रांस के आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं।

31 साल पहले की तस्वीर

पहले बात 31 साल पहले की करते हैं। जब दुनिया की इकोनॉमी अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों के इर्द-गिर्द ही घूमती थी। उस समय भारत की इकोनॉमी का नाम कहीं भी नहीं लिया जाता था। आंकड़ों की बात करें तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिसटिक्स के अनुसार फ्रांस की इकोनॉमी साल 1992 में 1.4 ट्रिलियन डॉलर की थी। उस समय फ्रांस ब्रिटेन की इकोनॉमी से भी आगे था। तब ब्रिटेन की इकोनॉमी 1.2 ट्रिलियन डॉलर की थी। वहीं बात भारत की करें तब यह दोनों देशों के मुकाबले में कहीं भी नहीं था। तब देश में नरसिम्हा राव की सरकार थी और देश के वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे। उस दौर में भारत ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया और दुनिया के तमाम देशों की कंपनियों का स्वागत करते हुए ग्लोबलाइजेशन का ऐलान किया। उस समय देश की कुल जीडीपी मात्र 0.28 ट्रिलियन डॉलर की थी। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर भारत ने दोनों के साथ कैसे मुकाबला किया और कितनी तेजी के साथ इन दोनों देशों को पछाड़ने का सफर तय किया।

बदल गई ग्लोबल इकोनॉमी की तस्वीर

साल 2023 खत्म हो चुका है. दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी की तस्वीर बदल चुकी है। आंकड़ें और मिजाज भी बदल चुका है। आज भारत दुनिया की टॉप-5 सुपर इकोनॉमिक पावर में से एक है। देश की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर के मुहाने पर खड़ी है। जी हां, भारत की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। जबकि यूरोप के सबसे बड़े देशों में शुमार फ्रांस की इकोनॉमी भी सिर्फ 3 ट्रिलियन डॉलर के आस-पास ही है, लेकिन वह भारत से काफी पीछे हैं। मौजूदा समय में फ्रांस की इकोनॉमी 3.05 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं बात ब्रिटेन की करें तो मौजूदा समय में ब्रिटेन की इकोनॉमी 3.33 ट्रिलियन डॉलर है. जोकि भारत से काफी कम है।

2024 में 4 ट्रिलियन का आंकड़ा होगा पार!

कई अनुमानों में कहा जा रहा है कि भारत की जीडीपी साल 2024 में 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर लेगी। वैसे इस साल भारत की इकोनॉमी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। जैसे जियो पॉटिकल टेंशन की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता का असर भारत समेत दुनिया के 50 राष्ट्रध्यक्षों के चुनाव भी आने वाले दिनों में इकोनॉमी को थोड़ा हिलाएंगे। अमेरिका भी इस साल ब्याज दरों में कटौती करेगा। जो इकोनॉमी को तो बूस्ट देगा, लेकिन इसका फायदा ऐसे दौर में ग्लोबल इकोनॉमी और भारत को मिल सकेगा। यह भविष्य के गर्भ में छिपा है। उसके बाद भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तमाम चुनौतियों के बाद भी भारत की इकोनॉमी पर उतना असर देखने को नहीं मिलेगा, जितना कयास लगाए जा रहे हैं।

दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी

वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ और ओईसीडी तक भारत को दुनिया में फास्टेस्ट इकोनॉमी का तमगा पहना चुके हैं। साल 2024 में भी यही होने वाला है।ओईसीडी के अनुसार भारत की इकोनॉमी वित्त वर्ष 2025 में 6.1 फीसदी पर रह सकती है। जबकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अनुसार यह आंकड़ा 6.1 फीसदी से लेकर 6.5 फीसदी तक रह सकता है। अगर बात आरबीआई की करें तरे वित्त वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7 फीसदी पर रह सकती है। जबकि वित्त वर्ष 2025 की पहली तीन तिमाहियों में ग्रोथ 6.7 फीसदी, 6.5 फीसदी और 6.4 फीसदी रह सकती है।

कर्ज में गले तक डूबी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

ठप हो सकता है सरकार का कामकाज!

नई दिल्ली। एजेंसी

अमेरिका में संघीय सरकार का कुल राष्ट्रीय कर्ज 34,000 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया है। कर्ज के इस स्तर से पता चलता है कि आने वाले वर्षों में सरकार को देश के बही-खाते को सुधारने के लिए राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। अमेरिकी वित्त विभाग ने मंगलवार को देश की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की है। यह राजनीतिक रूप से बंटे देश के लिए तनाव पैदा करने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार, बिना वार्षिक बजट के सरकार के कामकाज के कुछ हिस्सा ठप हो सकता है। रिपब्लिकन सांसदों और व्हाइट हाउस ने पिछले साल जून में देश की ऋण सीमा को अस्थायी रूप से हटाने पर सहमति व्यक्त की थी, जिससे ऐतिहासिक चूक या 'डिफॉल्ट' का जोखिम टल गया था. यह समझौता जनवरी, 2025 तक चलेगा।

कर्ज अनुमान से भी तेज बढ़ा

अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज कहीं अधिक तेजी से बढ़ा है। कांग्रेस के बजट कार्यालय ने जनवरी, 2020 में वित्त वर्ष 2028-29 में सकल संघीय ऋण 34,000 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान लगाया था। लेकिन 2020 में शुरू हुई कोविड महामारी की वजह से कर्ज इस स्तर पर अनुमान से कई साल पहले पहुंच गया है।

फिलहाल कोई असर नहीं

राष्ट्रीय कर्ज का फिलहाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर कोई बोझ नहीं दिख रहा है, क्योंकि निवेशक संघीय सरकार को कर्ज देने को तैयार हैं। यह कर्ज सरकार को कर बढ़ाए बिना कार्यक्रमों पर खर्च जारी रखने की अनुमति देता है। हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले दशकों में कर्ज का यह रास्ता राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई बड़े कार्यक्रमों को जोखिम में डाल सकता है।

जापान पर सबसे बड़ा कर्ज

अगर डॉलर या फिस्कल टर्म्स में देखा जाए जो सबसे अधिक राष्ट्रीय कर्ज यूएस पर है। लेकिन इसे अगर जीडीपी के अनुपात में देखा जाए तो जापान दुनिया के विकसित देशों में सबसे ज्यादा कर्ज वाला देश है। जापान पर उसकी जीडीपी के मुकाबले 260 फीसदी कर्ज है. वही यूएस पर उसकी जीडीपी के मुकाबले 121 फीसदी कर्ज है।

देश के विदेशी मुद्रा भंडार में तूफानी उछाल

21 महीने के रेकॉर्ड स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली। एजेंसी

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 22 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 4.471 अरब डॉलर बढ़कर 620.441 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पिछले सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 9.112 अरब डॉलर बढ़कर 615.971 अरब डॉलर हो गया था। यह किसी एक सप्ताह में हुई सर्वाधिक वृद्धि में से एक था। इससे पिछले सप्ताह में कुल मुद्रा भंडार 2.816 अरब डॉलर बढ़कर 606.859 अरब डॉलर रहा था। अक्टूबर, 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया था।

इस तरह 620 अरब डॉलर के मौजूदा स्तर पर विदेशी , मुद्रा भंडार अपने शिखर से केवल 25 अरब डॉलर दूर है। पिछले साल से वैश्विक घटनाक्रों की वजह से पैदा हुए दबाव के बीच आरबीआई ने रुपये को समर्थन देने के लिए बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया था। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, इस साल विदेशी मुद्रा भंडार में 57.634 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 22 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा विदेशी मुद्रा आस्तियां 4.898 अरब डॉलर बढ़कर 549.747 अरब डॉलर हो गयीं। डॉलर में अभिव्यक्त की जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में घट-बढ़ के प्रभावों को शामिल किया जाता है।

हालांकि, रिजर्व बैंक के अनुसार स्वर्ण भंडार का मूल्य 10.7 करोड़ डॉलर घटकर 47.474 अरब डॉलर रह गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) लगभग अपरिवर्तित रहा और यह मात्र 40 लाख डॉलर बढ़कर 18.327 अरब डॉलर हो गया। आलोच्य सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के पास रखा देश का मुद्रा भंडार 12.9 करोड़ डॉलर घटकर 4.894 अरब डॉलर रह गया।

सुखी वैवाहिक जीवन का आधार गौरी-शंकर रुद्राक्ष

आज के समय में पति-पत्नी के बीच अनावश्यक तनाव देखा जाता है, तनाव के कई कारण हो सकते हैं जिसमें एक-दूसरे की आदतें, आस-पास के लोगों का हस्तक्षेप तथा जन्मकुण्डली में स्थित ग्रह और ग्रहों का गोचर प्रमुख माने गए हैं। कभी-कभी आदतों में परिवर्तन कर दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। अक्सर प्रेम विवाह में जन्मपत्री का मिलान नहीं कराया जाता है और कभी-कभी जन्म समय सही से ज्ञात न होने पर पुकारने के नाम की राशि अथवा त्रुटिपूर्ण जन्मपत्री मिलान के कारण दाम्पत्य जीवन में आए दुखों के निवारण के लिए ग्रह शांति, मंगल दोष, नाड़ी दोष, भकूट दोष, गण दोष के निवारण करने से अनबन में कमी आती है। चाहें दाम्पत्य जीवन का क्लेश अथवा कोई भी संकट क्यों न हो, पूजा-पाठ, उपाय, रुद्राक्ष आदि धारण करने से ईश्वर कृपा से समस्या का निवारण होता है, बस उपाय के उपर आपके मन में सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास का होना जरूरी है।

डॉ. संतोष वाधवानी
रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता

कभी-कभी पति-पत्नी एक-दूसरे की शिकायत करते हुए कहते हैं, कि उनके जीवनसाथी को किसी ने अपने वश में कर लिया है, अर्थात् सम्मोहित कर लिया, ऐसी अवस्था में रुद्राक्ष धारण करना काफी मददगार साबित होता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष धारण करने वाले को कोई भी व्यक्ति सम्मोहित नहीं कर सकता, यहां तक कि भूत-प्रेत आदि के भय से भी छुटकारा मिलता है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अनेक उपाय ज्योतिष शास्त्र, वास्तु विज्ञान, लाल किताब आदि में वर्णित हैं, जिनमें रत्न, यंत्र, मंत्र, रुद्राक्ष, औषधि आदि का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। कुछ रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं, ये जुड़वां रुद्राक्ष भी वृक्ष पर ही होते हैं। प्राकृतिक तौर पर परस्पर दो जुड़े रुद्राक्षों को ''गौरी शंकर'' रुद्राक्ष कहा जाता है।

गौरीशंकर रुद्राक्षं तदेव प्रियदैवतम्।
धारणात्सुखसंपत्तिर्महदारोग्यमुत्तमम्॥

जुड़वां रुद्राक्षों की यह प्राकृतिक स्थिति दिव्य एवं अलौकिक शक्तियों से सम्पन्न है। घर, ऑफिस, तिजोरी, पूजा ग्रह, दुकान, गल्ले आदि में यह अद्भुत रुद्राक्ष मंगलकामना सिद्धि के लिए रखना लाभदायक है। श्रद्धा, विश्वास एवं सही विधि-विधान द्वारा अभिमंत्रित गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने वाले को शिव-शक्ति दोनों की कृपा तो प्राप्त होती ही है साथ में आध्यात्मिक सिद्धि एवं भौतिक सुख-सम्पन्नता का मार्ग भी प्रशस्त होता है। गौरीशंकर रुद्राक्ष की मुख्य विशेषताएं -

यह शिव पार्वती का स्वरूप है।

पारिवारिक सुख-शांति बढ़ाने के लिए गौरी-शंकर रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए।

पति-पत्नी के आपसी सम्बंध मजबूत करने के लिए इस रुद्राक्ष को शुभ मुहूर्त में अभिमंत्रित करके पति और पत्नी दोनों को एक ही साथ धारण करना चाहिए, ऐसा करने से पति-पत्नी के बीच राग, द्वेष, कलह, क्लेश दूर होने लगते हैं। गौरी-शंकर रुद्राक्ष धारण करने से जीवनसाथी को एक-दूसरे का परस्पर सहयोग प्राप्त होता है एवं सम्मान तथा प्रेम में वृद्धि होती है।

न केवल दाम्पत्य सुख वृद्धि के लिए बल्कि धनागमन एवं व्यापार उन्नति के लिए भी गौरी-शंकर रुद्राक्ष की उपयोगिता सर्वोपरि मानी गई है।

सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह रुद्राक्ष अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है।

गौरी-शंकर रुद्राक्ष को पूजाघर अथवा तिजोरी में रखना विशेष लाभदायक माना जाता है।

ऐसे जानिए कहीं आपके घर में वास्तुदोष तो नहीं... रखें इन बातों का ध्यान

डॉ. आर.डी. आचार्य
9009369396
ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ इंदौर (म.प्र.)

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में वास्तुदोष और वास्तु संबंधी नियमों का विशेष महत्व होता है। वास्तु शास्त्र के अनुनसार घर और आसपास जगहों पर अगर वास्तु संबंधी कोई भी दोष होता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर जरूर पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिन स्थानों पर वास्तु दोष होता है वहां पर नकारात्मकता और दरिद्रता का वास रहता है। वास्तु दोष होने पर आर्थिक परेशानियों के साथ-साथ तरह-तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। वास्तु दोष होने पर घर में सुख और शांति का हमेशा अभाव बना रहता है। वहीं जिन घरों में वास्तु दोष नहीं होता वहां पर हमेशा सुख-समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। आइए जानते हैं कैसे मालूम करें कि कहीं आपके घर में तो वास्तु संबंधी कोई दोष तो नहीं है।

घर के मुख्य द्वार की दिशा

वास्तु शास्त्र में दिशाओं का विशेष महत्व होता है। दिशा के अनुसार ही घर का निर्माण और घर में रखी हुई चीजों का वास्तुशास्त्र में खास महत्व होता है। सही दिशा में घर की स्थिति होने पर वास्तु दोष नहीं होता है। वास्तु शास्त्र में दक्षिण की दिशा को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो इससे आपके घर में हमेशा ही वास्तु दोष बना रह सकता है। अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो इस वास्तु दोष को खत्म करने के लिए घर के द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा और दिक्दोषनाशक यंत्र वास्तुदोष निवारण का महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है। इस उपाय से घर में वास्तु दोष से बचा जा सकता है।

घर के मंदिर की दिशा

हिंदू धर्म में घर में बने मंदिर का विशेष महत्व होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मंदिर के स्थान पर सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा हमेशा मौजूद रहती है। वास्तुशास्त्र में घर के मंदिर की दिशा ईशान कोण यानी उत्तर-पूर्व को सबसे शुभ माना गया है। ऐसे में अगर आपके घर में बना मंदिर दक्षिण या पश्चिम दिशा में है तो यह अशुभ माना जाता है और इससे घर में वास्तु दोष पैदा हो सकता है। ऐसे में आपको इस दिशा में मंदिर को कभी भी भूलकर नहीं रखना चाहिए। गलत दिशा में रखें मंदिर से घर के सदस्यों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

टूटी-फूटी चीजों का घर पर होना

वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में टूटे-फूटे और बेकार हो चुके बर्तन या सामान रखे हुए हैं तो इससे वास्तु दोष पैदा हो सकते हैं। वास्तु में टूटे-फूटे चीजों में दरिद्रता का निशानी मानी जाती है। इससे पूरे घर में वास्तु दोष बना रहता है। ऐसे में अगर आपके घर में बेकार हो चुके बर्तन को फौरन ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए।

बिखरा हुआ सामान

जिन घरों में हमेशा चीजें बिखरी हुई होती हैं वहां पर वास्तु दोष हो सकता है। इससे घर में आर्थिक परेशानियों के साथ मानसिक परेशानियां भी बनी रहती हैं।

11 जनवरी से पिता-पुत्र ग्रह देंगे इन राशियों का साथ, व्यापार, प्रेम और नौकरी में रहेगी लाभकारी स्थिति

पं. राजेश वैष्णव
शनि उपासक ज्योतिष रत्न एवं वास्तु विशेषज्ञ
98272 88490

प्रत्येक ग्रह एक निश्चित अवधि तक एक राशि में रहने के बाद राशि परिवर्तन करता है। सभी ग्रह का गोचर काल अलग-अलग होता है। कभी एक ही राशि में दो से अधिक ग्रह एक साथ आते हैं। ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के गुणों का फल जातकों को भुगतना पड़ता है। 15 जनवरी को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा।

शनि देव पूरे एक साल तक कुंभ राशि में रहेंगे। 11 जनवरी को सूर्य देव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इस दिन शनि शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। दोनों ग्रहों के परिवर्तन का असर सभी राशियों पर पड़ेगा। सूर्य-शनि पिता पुत्र हैं, फिर भी उनके बीच कटुता

है। उनका एक साथ आना परेशानी भरा है, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए आशीष लेकर आएगा।

मेष राशि

इस राशि के जातकों के लिए नक्षत्र परिवर्तन की स्थिति लाभकारी रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। कड़ी मेहनत से अपेक्षित सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर कामकाज की वाहवाही होगी। अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए समय उचित है। व्यापार में परेशानियों से राहत मिलेगी।

सिंह राशि

नक्षत्र परिवर्तन से सिंह राशिवालों को लाभ मिलेगा। हाथ में लिया गया काम चुटकियों में पूरा होगा। पारिवारिक स्तर पर खुशी का माहौल रहेगा। सूर्यदेव की कृपा से समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा। हर संकट का धैर्य से सामना करने की शक्ति मिलेगी। अनुभवी लोगों से नई जानकारियां हासिल होंगी।

तुला राशि

तुला राशि के साधकों का आत्मविश्वास प्रबल होगा। पारिवारिक स्तर पर रिश्ते मजबूत होंगे। नजदीकी लोगों से चल रही गलतफहमियां दूर होगी। ऑनलाइन गतिविधियों से बेहतरीन जानकारी मिलेगी। सामाजिक सीमाएं बढ़ेंगी और व्यक्तित्व बेहतर होगा।

नए साल से बदल लें ये चार आदतें, खुल जाएंगे समृद्धि के दरवाजे

आचार्य पं. संजय वर्मा
9826380407
ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ, इंदौर (म.प्र.)

हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इनमें से कुछ को सफलता हाथ लग जाती है, तो कई को मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता है। ऐसे में कुछ उपय किए जा सकते हैं। नया साल बस कुछ दिनों में शुरू होगा। साल 2024 में कुछ आदतें बदलने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकता है।

जीवन में बुरी आदतों के कारण मेहनत के बावजूद सपने अधूरे रह जाते हैं। दिन-रात मेहनत के बाद भी व्यक्ति रंक रह जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसर, कुछ आदतें सफलता में बाधक बन सकती हैं। अगर इसे बदल लें तो व्यक्ति का भाग्य सूरज की रोशनी की तरह चमक उठता है।

घर और खुद को साफ रखें

देवी लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं, जहां स्वच्छता होती है। जो जातक साफ सुथरा रहता है। वह धन को आकर्षित करता है। किचन में कभी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। इस कारण पैसा आता है, लेकिन टिकता नहीं है।

जरूरतमंद की मदद करें

सनातन धर्म में दान का महत्व है। जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति को धन की समस्या नहीं होती है। वेदों और पुराणों में अपनी क्षमतानुसार दान देने और मदद करने का उल्लेख है।

महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान

जहां औरतों और वृद्धजनों का सम्मान किया जाता है। वहां धन की कमी नहीं होती है। ऐसे घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसके अलावा जो लोग सुबह गाय को रोटी खिलाते हैं। उनके घर पर देवताओं की कृपा रहती है।

जीवनशैली का ग्रहों से संबंध

जीवनशैली का सीधा असर कुंडली और ग्रहों पर पड़ता है। शुभ कर्म के कारण ग्रह अच्छी स्थिति में रहते हैं। व्यक्ति के बुरे कर्म और आलस्य सफलता में बाधा बनते हैं। इसके अलावा बीमारी और मानसिक नकारात्मकता लाते हैं।

बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने 8.85% तक के डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट अनुभव के साथ नए साल का उत्साह बढ़ाया

बजाज फिनसर्व की ऐप और वेबसाइट के माध्यम से बुक की गई डिपॉजिट पर 8.85% की उच्च दर की पेशकश

पुणे/मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

देश के सबसे बड़े वित्तीय सेवा समूहों में से एक, बजाज फिनसर्व का हिस्सा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने आज डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) लॉन्च करने की घोषणा की, जो इसके ऐप और वेबसाइट के माध्यम से बुक की गई डिपॉजिट पर 8.85ऱ तक की विशेष दरें उपलब्ध कराता है। साल के अंत के साथ, डिजिटल एफडी ग्राहकों को डिपॉजिट बुक करने के लिए डिजिटल एवं असिस्टेड डिजिटल मोड का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके बचत के अनुभव को रूपांतरित करता है। बजाज फिनसर्व ऐप और वेबसाइट का सफ़र सरल, सुरक्षित और निर्बाध है जिसमें लगभग तुरंत एफडी बुकिंग की जा सकती है।

2 जनवरी, 2024 से प्रभावी, बजाज फाइनेंस वरिष्ठ नागरिकों को बजाज फिनसर्व ऐप और वेब पर बुक की गई एफडी में 42 महीने की अवधि के लिए 8.85ऱ प्रति वर्ष तक की ब्याज दर प्रदान कर रहा है। 60 वर्ष से कम उम्र के जमाकर्ता प्रति वर्ष 8.60 प्रतिशत तक कमा सकते हैं। संशोधित दरें 42 महीने की अवधि के लिए 5 करोड़ रुपये तक की नई जमा और परिपक्व होने वाली जमाराशियों के नवीनीकरण पर लागू होंगी।

बजाज फाइनेंस के फिक्स्ड डिपॉजिट और निवेश प्रमुख सचिन सिक्का ने कहा, 'हमारी बाधारहित प्रक्रियाएं, आकर्षक ब्याज दरें और ग्राहक अनुकूल नीतियां बजाज फाइनेंस एफडी के साथ उपभोक्ता के अनुभवों को और बेहतर बनाती हैं। 2 वर्षों में हमारी डिपॉजिट बुकिंग में 2 गुना वृद्धि भी बजाज ब्रांड पर ग्राहकों के भरोसे का प्रमाण है। हमारे एफडी अब जमाकर्ताओं को डिजिटल-फर्स्ट सोचने में सक्षम बनाते हैं। इसे एक सरल एंड-टू-एंड डिजिटल सफ़र के रूप में बनाया गया है, जिसमें विशेष रूप से बजाज फिनसर्व ऐप और वेब पर उच्च ब्याज दरें उपलब्ध हैं। यह एफडी खोलने के अनुभव को डिजिटल युग में लाता है।

30 सितंबर, 2023 तक बजाज फाइनेंस के ऐप प्लेटफॉर्म पर 44.68 मिलियन नेट उपयोगकर्ताओं के साथ 76.56 मिलियन ग्राहक जुड़े हैं। data.io की रिपोर्ट के अनुसार बजाज फिनसर्व ऐप भारत में प्लेस्टोर पर वित्तीय क्षेत्र में 4 था सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। 30 सितम्बर, 2023 तक यह कंपनी 54,821 करोड़ रुपये और 1.4 मिलियन से अधिक डिपॉजिट की समेकित डिपॉजिट बुकिंग के साथ देश की सबसे बड़ी जमा लेने वाली एनबीएफसी बनकर उभरी है। बजाज फाइनेंस की फिक्स्ड डिपॉजिट प्रोग्राम को CRISIL की AAA/स्टेबल और ICRA की AAA (स्टेबल) के साथ उच्चतम स्थिरता रेटिंग प्राप्त है, जो निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक है। कंपनी की ऐप एक निवेश बाज़ार भी प्रदान करता है जहां ग्राहक म्यूचुअल फंड की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कर सकते हैं।

अंबानी और टाटा भी बेचने लगे अब सस्ती सरकारी दाल

जानिए क्या है कीमत

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकारी एजेंसी Nafed ने पहली बार सरकारी सब्सिडी वाले अनाज को प्राइवेट रिटेलर के जरिए उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया है। इसके लिए रिलायंस रिटेल और बिग बास्केट प्लैटफॉर्म पर भारत दाल ब्रांड के तहत सब्सिडी वाली दाल की बिक्री शुरू भी कर दी गई है। भारत चना दाल इन रिटेलर द्वारा बेची जाने वाली सबसे कम कीमत वाली दाल से भी 40% से अधिक सस्ती है। जल्द ही प्राइवेट रिटेलर के जरिए भारत आटा की बिक्री शुरू करने की भी योजना है। देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल भारत और एशिया के सबसे बड़े रईस मुकेश अंबानी की कंपनी है जबकि बिग बास्केट का मालिकाना हक टाटा डिजिटल के पास है।

Nafed के अधिकारियों ने बताया कि रिलायंस ने अक्टूबर के अंत से भारत दाल की बिक्री शुरू कर दी, जिसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सूत्रों ने कहा कि रिलायंस के कुछ स्टोर पर भारत दाल की बिक्री वहां होने वाली चना दाल की कुल बिक्री का करीब 50% है। सूत्रों का कहना है कि सब्सिडी वाली चना दाल के कारण स्टोर पर मौजूद प्राइवेट लेबल वाली दाल की बिक्री में दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकारी दबाव के कारण निजी रिटेलर भारत दाल बेचने पर सहमत हो गए हैं।

चने का स्टॉक

रिपोर्ट के अनुसार, भारत चना दाल की बिक्री उत्तर और पश्चिम भारत में ज्यादा हो रही है, जहां नेफेड भारत दाल को प्रोसेस्ड करवा रहा है। सूत्रों ने बताया कि भारत दाल और प्राइवेट लेबल दाल की गुणवत्ता में ज्यादा अंतर नहीं है क्योंकि दोनों को Nafed से चना मिलता है। Nafed भारत की एकमात्र एजेंसी है जिसके पास चने का स्टॉक है।

राम मंदिर-राम दरबार की छाप वाले सोने-चांदी के सिक्कों की बढ़ी डिमांड

जमकर खरीदारी कर रहे लोग

नई दिल्ली। देश में अचानक से राम मंदिर और राम दरबार वाले सोने-चांदी के सिक्कों की डिमांड काफी बढ़ गई है। इनमें काफी उछाल आया है। लोग जमकर राम मंदिर और राम दरबार वाले सिक्कों की खरीदारी कर रहे हैं। अयोध्या में जैसे-जैसे अभिषेक समारोह की तारीख नजदीक आ रही है। इन सिक्कों की डिमांड उससे ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले अभिषेक समारोह से पहले ज्वैलर्स के पास राम मंदिर और राम दरबार की छाप वाले सोने और चांदी के सिक्कों की भारी मांग देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश ज्वैलर्स एसोसिएशन के महासचिव पुष्पेंद्र जायसवाल ने बताया कि चांदी के राम दरबार की बाजार में काफी मांग है।

जमकर मिल रहे ऑर्डर

पुष्पेंद्र जायसवाल के मुताबिक, अकेले कानपुर में ज्वैलर्स को राम मंदिर और राम दरबार (लक्ष्मण, सीता और हनुमान के साथ राम) और विभिन्न आकारों में भगवान राम की 1,000 मूर्तियों को दर्शाने वाले 5,000 सिक्कों के ऑर्डर मिले हैं। कुछ जौहरी राम मंदिर की प्रतिकृति वाले सोने के छोटे सिक्के भी बेच रहे हैं। जायसवाल ने कहा, वजन के हिसाब से राम दरबार चांदी के सिक्के की कीमत 900 रुपये से 25,000 रुपये तक है।

800 करोड़ का कारोबार

ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्डस्मिथ्स फेडरेशन के अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि उनका अनुमान है कि प्रतिष्ठा समारोह से शहर में लगभग 800 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ है। चूंकि जनवरी के मध्य से शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है, इसलिए राम मंदिर वाले सिक्के सबसे पसंदीदा उपहार विकल्पों में से एक के रूप में उभर रहे हैं। स्थानीय जौहरी रतुल रस्तोगी ने कहा, 'शादी के इस मौसम में भगवान राम की मूर्तियों की भी काफी मांग है।'

मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ार्मास्यूटिकल्स साइंसेज़ को एन.बी.ए अवार्ड

■पूरे इंदौर में लगभग 40 फ़ार्मेसी कॉलेज हैं जिसमें मात्र मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ार्मास्यूटिकल्स साइंसेज़ को एन.बी.ए एवार्ड मिला है। ■पूरे मध्य प्रदेश में कुल 6 फ़ार्मेसी कॉलेजों को ही मिला है एन.बी.ए एक्रिडिटेशन ■मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ार्मास्यूटिकल्स साइंसेज़ के बी.फ़ार्मा कोर्स को मिला यह उत्कृष्ट राष्ट्रीय मानक। ■बी. फ़ार्मा के साथ-साथ मॉडर्न ग्रुप में एम.फ़ार्मा, डी.फ़ार्मा, एम.बी.ए फ़ार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, एम.बी.ए, बी.बी.ए, बी.कॉम, बी.एड आदि कोर्सेज़ का भी संचालन किया जाता है।

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

मॉडर्न इंस्टिट्यूट ऑफ़ फ़ार्मास्यूटिकल साइंसेज इंदौर के बी फार्मा बैचलर डिग्री कोर्स को नेशनल बोर्ड का एक्रीडिटेशन एमबीए द्वारा एक्रेडिटेड किया गया है आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में संस्था के अध्यक्ष डॉ0 अनिल खरया ने बताया कि मॉडर्न इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एकमात्र ऐसा फ़ार्मेसी कॉलेज है जो फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द्वारा सपोर्टेड है तथा इंडस्ट्री एवं इंस्टिट्यूट इंटरफ़ेस का सबसे अच्छा उदाहरण है।डॉ. खरया ने बताया कि नेशनल बोर्ड आफ एक्रीडिटेशन द्वारा पूरे इंदौर में मात्र मॉडर्न इंस्टीट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज को एनबीए एवार्ड किया गया है जो कि गर्व का विषय है। यह भी बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में केवल 6 फ़ार्मेसी संस्थाओं को एनबीए एक्रीडिटेशन किया गया है अब इन 6 फार्मेसी महाविद्यालयों में मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ार्मास्यूटिकल्स साइंसेज़ का नाम भी शुमार है। संस्था के समूह निदेशक डॉ. पुनीत कुमार द्विवेदी ने बताया कि नैशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडिटेशन (एन.बी.ए) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट गुणवत्ता मापकों के आधार पर संस्थानों को एक्रिडिटेट किया जाता है जिसे एव.बी.ए एवार्ड कहा जाता है। गुणवत्ता के इन मापकों में शोध एवं नवाचार, उत्कृष्ट शिक्षा, उद्यमिता एवं कौशल विकास, कैंपस की गतिविधियों, इंडस्ट्री कनेक्ट आदि को विशेष रूप से ध्यान में रखकर विशेषज्ञों द्वारा संस्थानों की जाँच की जाती है। बतादें कि मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ार्मास्यूटिकल्स साइंसेज़ के बी. फ़ार्मा कोर्स को वर्ष 2026 तक के लिये एन.बी.ए एवार्ड किया गया है। वर्तमान में पूरे इंदौर में केवल मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ार्मास्यूटिकल्स साइंसेज़ ही एन.बी.ए. एक्रिडिटेटेड संस्थान है। संस्था से अध्यक्ष श्री अरूण खरया, चेयरमैन डॉ. अनिल खरया एवं उपाध्यक्ष श्री शांतनु खरया ने मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ़ फ़ार्मास्यूटिकल्स साइंसेज़ की विभागाध्यक्ष डॉ. सपना मालवीया, सभी फ़ैकल्टी एवं स्टॉफ को इस महान उपलब्धि के लिये बधाई दी।डॉ. सपना मालवीय ने सभी टीम सदस्यों की मेहनत एवं समन्वय को साधुवाद दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्थान की ओर से प्रो0 डॉ. गिरीश अग्रवाल (समन्वयक- एम.बी.ए फ़ार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट), डॉ. नेहा शर्मा चौधरी (हेड एडमिशन्स) आदि उपस्थित रहे।

NBA Accreditation to Pharmacy-UG Course of Modern Institute of Pharmaceutical Sciences, Indore (M. P)

रिन्यू द्वारा सर्दियों में दो लाख कम्बल बांटे जायेंगे

उज्जैन। एजेंसी

अग्रणी डीकार्बनाइजेशन समाधान प्रदान करने वाली कंपनी, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी ने गिफ्ट वार्म्थ का 9वाँ संस्करण शुरू करने की घोषणा की है। यह कड़ाके की ठंड में समाज के वंचित वर्गों की सहायता करने की एक पहल है। इस साल, रिन्यू ने दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों में 2,00,000 से अधिक कम्बल बाँटने के लिए स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया है। यह कम्बल वितरण अभियान जनवरी तक चलेगा, ताकि सबसे अधिक ठंड पड़ने के दौरान इसका अधिकतम फायदा मिल सके। इस वर्ष रिन्यू राजस्थान में 37000 कंबल वितरित करेगा।

हाल के वर्षों में उत्तर भारत के राज्यों में जलवायु परिवर्तन के कारण चिलचिलाती ठंड पड़ती है, जिससे बेघर लोगों पर शीत लहर की भीषण मार पड़ती है। सरकारी आँकड़ों के अनुसार सर्दियों के दौरान लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसके कारण मौत तक हो जाती है। रिन्यू के कर्मचारी सरकारी अधिकारियों के सहयोग से निर्दिष्ट जिलों में शीत लहर से प्रभावित सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोगों को चिन्हित करके उनके जीवन में राहत पहुंचाने के लिए कम्बलों का वितरण करेंगे। यह वितरण अभियान जिला स्तर पर आरम्भ किया जाएगा, और आगे तहसील से ग्राम स्तर तक पहुँचेगा। इसके अलावा, कंपनी के कर्मचारी कम्बल वितरण के लिए रात्रिकालीन अभियान चलाएंगे तथा दान के माध्यम से आश्रय स्थलों में योगदान करेंगे। इन कम्बलों को छोटे पैमाने के कारोबारियों से प्राप्त किया गया है जिसका उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

सस्टेनेबिलिटी की को-फाउंडर और चेयरपर्सन, वैशाली निगम सिन्हा ने कहा कि, 'हाल के वर्षों में जलवायु संकट के कारण शीत लहर की तीव्रता बढ़ी है। मौसम में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण लाखों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रिन्यू में हम हमेशा समुदायों को लौटाने में यकीन करते आए हैं और गिफ्ट वार्म्थ कड़ाके की ठंड के महीनों में वंचित वर्गों के साथ खड़े होने की दिशा में हमारा एक छोटा कदम है। इस साल, हमने ज्यादा से ज्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचने की अपनी कोशिशों को तेज किया है। हमें अपने कर्मचारियों पर गर्व है जो इस पहल में पूरी लगन से जुड़कर इस प्रयास को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों के साथ ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं।

चालू खाते का घाटा मौजूदा वित्त वर्ष में घटकर जीडीपी के एक प्रतिशत पर रहने का अनुमान : रिपोर्ट

मुंबई। एजेंसी

अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्श ने मंगलवार को कहा कि मजबूत पूंजी प्रवाह के साथ भारत का वैश्विक स्तर पर लेन-देन से संबद्ध बही-खाता उम्मीद की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। इसको देखते हुए चालू खाते का घाटा (कैड) मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 में कम रहेगा और इसके जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के एक प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। इससे 39 अरब डॉलर का भुगतान अधिशेष की स्थिति होगी।

गोल्डमैन सैक्श ने एक रिपोर्ट में कहा कि चालू खाते का घाटा कम होने, मजबूत पूंजी प्रवाह, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और कम विदेशी कर्ज के साथ देश का वैश्विक स्तर पर लेन-देन से संबद्ध बही-खाता अनुकूल रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार, इसके साथ,

अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के इस साल नीतिगत दर में कटौती को देखते हुए बाह्य मोर्चे पर भारत की स्थिति बेहतर रहने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज कंपनी ने इन चीजों को देखते हुए चालू खाते के घाटे (कैड) के अनुमान को संशोधित कर इसके जीडीपी का एक प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जो पहले 1.3 प्रतिशत था। वहीं 2024-25 के लिए इसके 1.3 प्रतिशत रहने की संभावना जतायी गयी है, जबकि पहले इसके 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।

रिपोर्ट में इसके लिए अन्य बातों के अलावा कच्चे तेल के दाम के अनुमान को 90 डॉलर प्रति बैरल से घटाकर 81 डॉलर प्रति बैरल किये जाने तथा सेवा निर्यात के उम्मीद से बेहतर रहने को बताया है। गोल्डमैन सैक्श ने इक्विटी पूंजी प्रवाह बेहतर रहने के साथ कुल मिलाकर पूंजी प्रवाह अच्छा रहने का अनुमान जताया है। इसकी वजह फेडरल रिजर्व के नीतिगत दर में कटौती का चक्र शुरू करने की संभावना, बॉन्ड के जेपी मॉर्गन के वैश्विक सरकारी बॉन्ड सूचकांक में शामिल होने से क्षेत्र में बेहतर निवेश प्रवाह तथा उच्च एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) है। इस पूंजी प्रवाह से 2024 में पहले के कर्ज की परिपक्वता अवधि पूरी होने के साथ शुद्ध कंपनी डॉलर कर्ज प्रवाह कम करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर, भुगतान संतुलन के मोर्चे पर 2023-24 में 39 अरब डॉलर के अधिशेष की स्थिति होगी। हालांकि, अगले वित्त वर्ष में इसके कम होकर 27 अरब डॉलर रहने का अनुमान है।

कान्ह का गंदा पानी क्षिप्रा में जाने से रोकने हेतु एसोसिएशन करेगा प्रयास उद्योगों को देंगे समझाईश

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

14 जनवरी मकर संक्राती पर्व के मद्देनजर उज्जैन के क्षिप्रा स्नान को लेकर उज्जैन में आने वाले श्रध्दालुओं के सुविधा को देखते हुए इंदौर प्रशासन को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सख्त आदेश दिये गये है कि किसी भी हाल में कान्ह नदी का पानी क्षिप्रा नदी में नही पहुंचे जिससे की क्षिप्रा में पवित्र स्नान करने वाले श्रध्दालुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे। इसी विषय को लेकर आज नगर निगम आयुक्त श्रीमती हर्षिका सिंह एवं अपर आयुक्त श्री सिध्दार्थ जैन द्वारा उद्योगपतियों व उद्योग संगठनों के पदाधिकारियों व निगम एवं प्रदूषण विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित कर उक्त आदेश और दिशा निर्देशो का पालन करने हेतु कहा।

अध्यक्ष श्री योगेश मेहता ने आयुक्त को बताया कि हमारा संगठन भी पूर्ण सतर्कता के साथ उद्योगो को समझाईश देगा वही निगम प्रशासन भी उद्योगों को समझाए की कान्ह नदी में पानी छोडे जाने के कई दुष्परिणाम हो रहे है, एसोसिएशन निगम को इस कार्य में पूर्ण सहयोग करेगा और उद्योगो को भी बतायेगा कि नियमित रूप से पानी टेंकरों के माध्यम से ईटीपी प्लांट पर भेजे। निगम की ओर से जानकारी दी गई कि इसके लिए निगम प्रशासन द्वारा कुछ उद्योगो को चिन्हित किया गया है जिसकी सूची भी जारी की है जिन्हें प्राथमिकता से पानी कान्ह नदी में नही छोडे जाने की हिदायत दी जाना आवश्यक है। बैठक में एसोसिएशन की ओर से सर्वश्री प्रकाश जैन, दिलीप देव, प्रमोद डफरिया, तरूण व्यास, हरीश नागर, प्रमोद जैन आदि सहित बरदरी, कुमेडी, सांवेर रोड के उद्योगपति उपस्थित थे।

आसान हुआ बंद बैंक खातों को चालू करना, RBI ने दी नियमों में ढील

नई दिल्ली। एजेंसी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने निष्क्रिय बैंक खातों को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया में ढील दी है। साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए नियमों को कुछ सख्त भी किया है, ताकि निष्क्रिय खातों से कोई रकम न निकाल सके। आरबीआई का कहना है कि अब निष्क्रिय खातों को दोबारा शुरू करने के लिए सिर्फ नो योर कस्टमर (केवाईसी) डिटेल्स जमा करनी होगी। केवाईसी डिटेल्स को बैंक की किसी भी ब्रांच में सबमिट किया जा सकता है। यह प्रक्रिया खाताधारक के अनुरोध पर विडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस (V-

CIP) के जरिए भी पूरी की जा सकती है।बैंक किसी भी खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए कोई शुल्क नहीं वसूल सकते। अगर कोई खाता निष्क्रिय हो गया है, तो बैंक उससे मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाली पेनल्टी भी नहीं लगा सकते। बैंकों को सेविंग अकाउंट पर ब्याज भी देते रहना होगा, चाहे वह निष्क्रिय क्यों न हो। इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने बैंकों को एक एनुअल रिव्यू भी करने का निर्देश दिया है, ताकि उन बैंक खातों का पता लगाया जा सके, जिनमें एक साल से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

कब से लागू होंगे दिशानिर्देश

आरबीआई ने अपने बयान में कहा, 'वित्तीय धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए निष्क्रिय खातों का पता लगाना जरूरी है। निष्क्रिय खाते जब दोबारा सक्रिय हो जाएं, तो उनसे होने वाले लेनदेन की कम से कम 6 महीने तक हाई लेवल पर निगरानी होनी चाहिए। इसका पता कस्टमर और बैंक स्टाफ को नहीं लगना चाहिए। इससे निष्क्रिय खातों के जरिए होने वाले फ्रॉड को कम करने में मदद मिलेगी।' आरबीआई के संशोधित दिशानिर्देश एक अप्रैल से लागू होंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक समेत सभी कमर्शल बैंकों को इन निर्देशों का पालन करना होगा।आरबीआई ने कहा कि बैंकों को सावधि जमा (टर्म डिपॉजिट) पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर इसे रिन्यू नहीं किया गया या कस्टमर ने मैच्योरिटी के बाद रकम नहीं निकाली या फिर अपने इसे अपने बचत/चालू खाते में ट्रांसफर नहीं किया, तो इस तरह के खातों को समीक्षा की जानी चाहिए, ताकि जमा राशि अनक्लेम्ड न रह जाए। अगर एक साल तक खातों में कोई लेनदेन नहीं होता, तो बैंकों को खाताधारक को सूचित करना होगा। अगर बैंकों को प्रतिक्रिया नहीं मिलती, तो उसकी वजह पता लगाने का दायित्व भी बैंकों का ही है। अगर खाताधारक की मौत हो चुकी है, तो उसके कानूनी वारिसों का पता लगाने के लिए जांच करना भी बैंकों का काम है।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।